



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052020-219358
CG-DL-E-12052020-219358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2020/वैशाख 22, 1942

No. 122]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2020/VAISAKHA 22, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2020

प्राथमिक जांच परिणाम

प्रकरण सं. एसजी - 07/2019

विषय: भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय)
नियमावली, 2017 के तहत कोरिया गणराज्य से "पॉलीबुटाडीन रबर" के आयातों के संबंध में
द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के प्राथमिक जांच परिणाम।

फा. सं. 22/7/2019-डीजीटीआर.— क. मामले की पृष्ठभूमि

1. भारत गणराज्य और कोरिया सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (जिसे यहां आगे "सीईपीए" कहा गया है) के अनुच्छेद 2.22 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (जिसे यहां आगे "नियमावली" अथवा "द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से पॉलीबुटाडीन रबर (जिसे यहां आगे "विचाराधीन

उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के बड़े हुए आयातों के संबंध में द्विपक्षीय सुरक्षा जांच की शुरुआत के लिए सीईपीए और द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली के अनुसार व्यापार सुधार महानिदेशक (जिसे यहां आगे "महानिदेशक" अथवा "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. महानिदेशक ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 7 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या एसजी-07/2019 जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. महानिदेशक ने 7 नवंबर, 2019 की जांच की शुरुआत की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और आवेदन पत्र में उल्लिखित ज्ञात आयातकों तथा अन्य पक्षकारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार भेजी।

ख. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों को नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार उपलब्ध कराई गई थी।

ग. महानिदेशक ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को द्विपक्षीय जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा तीस दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया:

i. कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स लि.

ii. एलजी केम लिमिटेड

घ. जारी प्रश्नावली के उत्तर में दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ङ. महानिदेशक ने नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

i. जे के टायर्स इंडस्ट्रीज लि.

ii. अपोलो टायर्स लि.

iii. एमआरएफ लि.

iv. सीईएटी लिमिटेड

v. बिरला टायर्स

vi. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लि.

vii. गुडईयर इंडिया लिमिटेड

viii. कांटीनैटल इंडिया लि.

ix. योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

x. मैट्रो टायर्स लिमिटेड

xi. रालसन इंडिया लिमिटेड

xii. ट्रेड्स डायरेक्ट लिमिटेड

xiii. इंडाग रबर्स लिमिटेड

च. जारी प्रश्नावली के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड
- ii. अपोलो टायर्स लिमिटेड
- iii. एमआरएफ लिमिटेड
- iv. सीईएटी लिमिटेड

छ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को भी प्रश्नावली भेजी। घरेलू उद्योग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ज. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देते हुए अनुरोध दायर किए:

- i. कोरिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
- ii. कोरिया सरकार
- iii. ऑल इंडिया रबर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

झ. महानिदेशक ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

ञ. अब तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां भी संगत पाए गए, पर इन प्राथमिक जांच परिणामों को जारी करते समय विचार किया गया है।

ग. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

4. आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पांच प्रकार के पॉलीबुटाडीन रबर हैं जिनमें से टाइटेनियम और लीथियम ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। पॉलीबुटाडीन रबर के टाइटेनियम ग्रेड की घटिया गुणवत्ता है और अप्रयोज्य हो गया है। लीथियम ग्रेड का प्रयोग प्लास्टिक रूप में किया जाता है। अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इन दोनों ग्रेडों को शामिल नहीं करता।

ख. आवेदन पत्र में चुनी गई अवधि बड़े हुए आयातों की मौजूदगी और उनकी क्षति के संबंध में लिए जाने वाले निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त रूप से लंबी है।

ग. विचाराधीन अवधि में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई छूट नहीं, प्रशुल्क में कमी तथा प्रशुल्क समाप्ति के बाद की अवधि शामिल होनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप है।

घ. विचाराधीन उत्पाद के आयात शुल्क रियायत में वृद्धि से इस अवधि में काफी वृद्धि दर्शाते हैं।

ङ. पिछले 12 वर्षों में सीईपीए के तहत दी गई रियायतों के कारण आयात लगभग 1093 गुना बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क शून्य होने पर आयात पिछले तीन वर्षों में दोगुने हो गए हैं।

च. संबद्ध सामानों के लिए मांग 2008-09 में थोड़ी सी गिरावट के साथ इस अवधि में बढ़ी है।

छ. मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा 4 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा 73 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत हो गया है।

ज. कोरियाई उत्पादक बाजार में कीमत निर्धारक हैं और घरेलू उद्योग तथा दूसरे देश के आयात उनके द्वारा निर्धारित कीमत पैटर्न को अपनाने के लिए मजबूर हैं।

झ. घरेलू उद्योग बिक्री लागत की सीमा तक बिक्री कीमतें बढ़ाने में असमर्थ हैं। वर्तमान कम कीमतें केवल संबद्ध देश के आयातों की कम कीमतों के कारण हैं।

ञ. उद्योग को 2014-15 से वित्तीय हानियां हो रही हैं।

- ट. घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव इस तथ्य से देखा जा सकता है कि उद्योग घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाया है और कम लाभप्रद निर्यातों पर जोर देने के लिए मजबूर रहा है।
- ठ. घरेलू उद्योग की मालसूची बड़ी है।
- ड. आयातों की मात्रा 2019-20 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में अधिक बढ़ी है।
- ढ. समायोजन योजनाओं के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे कीमतें कम करने के लिए उपाय कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना दी है जिसमें उत्प्रेरक एवं रसायन लागत कमी करने संबंधी कार्रवाई, परिवर्तन लागत में कमी, प्रसंस्करण दक्षता में सुधार, खपत मानदंडों में सुधार, परिवहन लागतों में कमी, स्टॉक के आमूल-चूल परिवर्तन में सुधार आदि शामिल हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ग्राहकों के परिसरों पर आयातों की पहुँच कीमत के आधार पर आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करता है, अतः कंपनी चार वर्षों की अवधि में कोरियाई आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धा हो जाएगी।

घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

घ.1 कोरिया पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन

5. कोरिया पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. संबद्ध आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि क्षति पाटन के कारण नहीं हुई थी। अतः उन्नत निष्पादन से अब गंभीर क्षति कैसे हो सकती है?
- ख. आवेदन पत्र का अगोपनीय रूपांतर 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहता है जो कि व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया है और सभी व्यापार उपचार जांचों के लिए लागू है। आवेदन पत्र में निहित आरोपों के उपयुक्त समझ के लिए आवेदन पत्र नहीं होने देता।
- ग. आवेदक को महानिदेशक द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात् अप्रैल, 2015 से जून, 2019 तक की अवधि के आधार पर संशोधित आंकड़े बताने चाहिए।
- घ. द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 4(2)(ख) में याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह अनिवार्य रूप से समायोजन योजना दायर करे। समायोजन योजना के अभाव में महानिदेशक द्वारा फथैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन), कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, अनरॉट एल्युमीनियम के अलॉय न किए गए इंगट तथा फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉल्यॉल में शुल्क लगाए जाने की सिफारिश नहीं की गई थी।
- ड. जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX में अप्रत्याशित गतिविधियां अपेक्षित हैं जिनसे आयातों में वृद्धि हो सकती है जिन्हें आवेदक याचिका में हल करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित गतिविधियों के रूप में नहीं मानी जा सकती, जैसा कि अर्जेंटीना-प्रीजर्व पीचेस मामले में पैनल द्वारा माना गया है।
- च. घरेलू उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। कोरिया गणराज्य से आयात मांग में वृद्धि से बढ़े हैं।
- छ. सीईपीए के अनुच्छेद 2.23 की अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं क्योंकि:
 - i. आयातों में तथाकथित वृद्धि कोरिया-भारत सीईपीए के तहत शुल्कों में कमी अथवा समाप्ति के परिणामस्वरूप नहीं है।
 - ii. पीबीआर के भारत में कोरियाई आयातों में हाल में, अचानक, तेज तथा काफी वृद्धि नहीं हुई है।
 - iii. पीबीआर के किसी भी तथाकथित बढ़े हुए आयातों से गंभीर क्षति अथवा उसका खतरा नहीं हुआ है; और
 - iv. पीबीआर के कोरियाई आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का पर्याप्त कारण अकेले नहीं हैं।

- ज. कोई गंभीर क्षति अथवा क्षति का खतरा नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 8(6)(ग) और (घ) तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(क) द्वारा परिभाषित है। वस्तुतः घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- झ. अनरॉट एल्युमीनियम के अलाय न किए गए इंगट, 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, बेयर इलेस्टोमेरिक फिलामेंट यार्न कुछ विगत जांचें हैं जहां महानिदेशक ने जांच को रद्द किया था क्योंकि उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ था।
- ञ. आवेदक ने वास्तविक लागत से अधिक लागत पर कच्ची सामग्री अंतरित की है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों की दावा की गई लागत में वृद्धि हुई।
- ट. करार के अनुच्छेद 4.2(ख) तथा नियमावली के नियम 7 के अनुपालन में महानिदेशक के लिए यह अपेक्षित है कि वे आयातों में वृद्धि और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच करें और गैर-आरोपण विश्लेषण करें।
- ठ. सीमा शुल्कों में कमी से घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ड. घरेलू उद्योग नियोडायमियम ग्रेड का उत्पादन नहीं करता जिसके कोरिया गणराज्य से प्रमुख आयात हैं। यहां तक कि उत्पादित हो तो उत्पाद औद्योगिक प्रयोक्ता गुणवत्ता प्रमाणन को पूरा अथवा पास नहीं करेगा। यह उत्पाद अंतिम प्रयोक्ता के लिए, विशेष रूप से वैश्विक टायर विनिर्माताओं के लिए प्रयोग में सीमित है।
- ढ. आसियान देशों से आयातों में वृद्धि की दर संबद्ध देश से आयातों की दर से अधिक है।
- ण. चूंकि आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, अतः शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं होगा। आवेदक बाजार में अपने लिए एक प्रभावी स्थिति सृजित करेगा और नए प्रवेशकों के लिए अवरोध तैयार करेगा।
- त. उत्पाद की कीमतें बुटाडीन की कीमतों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, अतः कीमतों में गिरावट आयात कीमत के कारण नहीं हो सकती।

घ.2 कोरिया सरकार द्वारा किए गए अनुरोध

6. कोरिया सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भारतीय घरेलू उद्योग की वर्तमान परिस्थितियां कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.24 के अनुसार अनंतिम रक्षोपाय लगाए जाने की आवश्यकता की महत्वपूर्ण परिस्थितियों के लिए योग्य नहीं हैं।
- ख. जांच को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि आवेदक ने कोई समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है जो कि कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.23(छ) और नियमावली के नियम 4(2)ख के तहत अनिवार्य रूप से दी जानी अपेक्षित है।
- ग. याचिका में आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों में अप्रैल-जून, 2019 की अवधि के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं।
- घ. घरेलू उद्योग की आयातित सामानों के उपयुक्त विकल्प प्रदान करने और मांग पूरा करने के लिए उसकी कम क्षमता के लिए असमर्थता के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं हो रही है।
- ङ. सूचीकरण के लिए 2007-08 से आंकड़ों की प्रस्तुति से घरेलू बाजार में गतिविधियों की अवास्तविक प्रस्तुति हुई है।
- च. आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि संबद्ध सामानों की पाटनरोधी शुल्क के अंतिम जांच परिणाम में जो आंकड़े उपलब्ध थे, वे प्रकट नहीं किये गये हैं।
- छ. सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, अतः उपाय लागू नहीं किए जा सकते।
- ज. आयातों में वृद्धि में योगदान करने वाला प्रमुख कारण सीईपीए के अनुसरण में उस अनुच्छेद के संबंध में शुल्कों में कमी अथवा समाप्ति होनी चाहिए। तथापि, वर्तमान जांच में वह नहीं है।
- झ. सीमा शुल्क की दर में 2010 से निरंतर गिरावट रही है, परंतु संबद्ध देश से आयात उस दर पर नहीं बढ़े। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण है।

- ज. बेयर इलेस्टोमेरिक फिलामेंट, फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलयाॅल, व्हाइट यैलो फॉस्फोरस कुछ ऐसी जांचें हैं जिनमें डीजीटीआर ने मांग-आपूर्ति अंतराल के आधार पर रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की है।
- ट. अन्य देशों से आयातों में कोरिया गणराज्य से आयातों की तुलना में तीव्र दर पर वृद्धि हुई है।
- ठ. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, एक सकारण एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए जो शुल्क में कमी और आयातों में आरोपित वृद्धि के बीच संबंध दर्शाए। महानिदेशक को चाहिए कि वे सकारण स्पष्टीकरण का पता लगाएं और बताएं तथा उसे दर्शाएं।
- ड. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 की भाषा के अनुसार आयातों में कोई अचानक, काफी अथवा तीव्र वृद्धि नहीं है।
- ढ. घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बाजार हिस्सा उत्पादन उत्पादकता, क्षमता उपयोग, बिक्री, लाभ तथा हानि और रोजगार जैसे सभी संगत मानदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।
- ण. जनवरी से सितंबर, 2019 तक भारत को पॉलीबुटाडीन रबर के कोरिया के हाल के निर्यात 13 प्रतिशत तक कम हुए हैं।

घ.3 ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

7. ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। संबद्ध सामानों के संबंध में हाल की पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि क्षति पाटन के कारण नहीं है, अतः आवेदक को सुधार हुए निष्पादन के बावजूद वर्तमान जांच में क्षति हुई नहीं हो सकती।
 - ख. आवेदक ने द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए शर्तें सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। अनुच्छेद 2.22 में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।
 - ग. आवेदक ने गलत सूचना के साथ गलत विवरण दिए हैं।
 - घ. आवेदन पत्र में आरोपों की उपयुक्त समझ नहीं मिलती क्योंकि वह व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है। डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार सूचना सभी व्यापार सुधार ढांचों के लिए लागू है।
 - ड. आवेदक ने द्विपक्षीय रक्षोपाय के नियम 4(2)(ख) के तहत अपेक्षित समायोजन योजना नहीं दी है। विगत में महानिदेशक ने फ्थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन), कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, अनरॉट एल्युमीनियम के अलाय न किए गए इंगट और फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलयाॅल में रक्षोपाय की सिफारिश नहीं की थी, जिनमें समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
 - च. आयातों की मात्रा में केवल वृद्धि को अप्रत्याशित घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। महानिदेशक के लिए उसकी जांच करना अपेक्षित था।
 - छ. अधिनियम की धारा 8(6)(ग) और (घ) के अनुसार गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की स्थिति नहीं है। इसके बजाए घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
 - ज. महानिदेशक ने अनरॉट एल्युमीनियम के अलाय न किए गए इंगट, 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, बेयर इलेस्टोमेरिक फिलामेंट यार्न में शुल्क की सिफारिश नहीं की थी जिनमें उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ था।
 - झ. बढ़ी हुई लागत आवेदक के वास्तविक लागत से अधिक लागत पर कच्ची सामग्री अंतरित करने के कारण है।
 - ञ. जांच में कारणात्मक संपर्क का अभाव है। प्राधिकारी को कारणात्मक संपर्क की जांच करनी चाहिए तथा गैर-आरोपण विश्लेषण करना चाहिए।
 - ट. आसियान देशों से आयातों में संबद्ध आयातों की तुलना में और तेज वृद्धि हुई है।

- ठ. घरेलू उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। कोरिया गणराज्य से आयात मांग में वृद्धि से बड़े हैं।
- ड. शुल्क लगाए जाने से आवेदक बाजार में अपने लिए प्रभावी स्थिति बना पाएंगे और नए प्रवेशकों के लिए अवरोध सृजित कर पाएंगे।

ऊ. महानिदेशक द्वारा जांच

8. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की जांच की है और प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- क. जहां तक अन्य आसियान देशों से आयातों का संबंध है, यह देखा जाता है कि अलग-अलग देशों से पूर्ण दृष्टि से आयातों की मात्रा कम है और इन देशों से आयातों की पहुँच कीमत कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत से अधिक है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि आयातों की मात्रा में प्रशुल्क रियायत में वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं हुई है। अतः प्राधिकारी ने प्रशुल्क रियायत से पूर्व, प्रशुल्क रियायत की अवधि और प्रशुल्क की समामि के बाद की अवधि के दौरान उत्पाद के आयातों की जांच की। संगत सूचना आवेदन पत्र में निहित है। यह देखा जाता है कि चूंकि रियायत बढ़ी, अतः कोरिया से आयातों की मात्रा बढ़ी। यह सिद्ध है कि प्रशुल्क रियायत में वृद्धि से कोरियाई आयात बड़े।
- ग. जहां तक पाटनरोधी मामले के संदर्भ का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी, परंतु वह पाटित आयातों के कारण नहीं थी। वस्तुतः पाटन का अभाव व्यापक रूप से भारत-कोरिया सीडीपीए के तहत कोरिया गणराज्य से आयातों पर दी गई प्रशुल्क रियायतों के कारण थी।
- घ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पाद की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत से निर्धारित की जाती है, यह नोट किया जाता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि शुल्क रियायत घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकती।
- ङ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को पूर्णतः वर्तमान आयातों के कारण क्षति लेनी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि नियम में यह उल्लेख नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति का पूरा कारण संबद्ध आयात होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के तर्कों के मद्देनजर प्राधिकारी ने रियायत पूर्व अवधि सहित लंबी अवधि में घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति की जांच की। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति वास्तविक रूप से खराब हुई है क्योंकि प्रशुल्क रियायत बढ़ी थी जबकि घरेलू उद्योग पूर्व में लाभ कमा रहा था, जब उत्पाद प्रशुल्क रियायतों के अध्येक्षीन नहीं था, घरेलू उद्योग को अब कोरियाई निर्यातों को प्रदान की गई प्रशुल्क रियायतों से वित्तीय हानियां हो रही हैं।
- च. जहां तक घरेलू उद्योग के बढ़ती हुई मांग के साथ क्षमताएं न बढ़ाए जाने के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान याचिका में प्रशुल्क रियायतों के निमित्त घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव के समाधान की ही मांग की गई है।
- छ. जहां तक समायोजन योजना का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद समायोजन योजना दी है।
- ज. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में अप्रैल, 2007 से मार्च, 2019 तक की अवधि के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरुआत का उत्तर देते हुए आवेदक ने सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों के पास संगत सूचना है और अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर है। प्राधिकारी ने बड़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2019 तक की अवधि मानी है। तथापि, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में वृद्धि करार के तहत शुल्क रियायतों का परिणाम है और परिणामस्वरूप क्षति पहुँचा रहे हैं,

प्राधिकारी ने याचिका में निहित लंबी अवधि के लिए अर्थात् अप्रैल, 2007 से आंकड़ों का उपयुक्त रूप से संदर्भ दिया है।

झ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के साथ पठित भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के तहत शुरू की गई एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या बड़े हुए आयात करार के तहत प्रशुल्क रियायतों का परिणाम हैं। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक उत्पाद के आयातों पर विचार किया है। यह देखा जाता है कि आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में बढ़ी है क्योंकि प्रशुल्क रियायतें बढ़ी थीं।

ञ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण बढ़े हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल ज्यादातर आयातों का औचित्य बना सकते हैं। तथापि, कोरिया से आयातों से पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ही कम नहीं है बल्कि कई देशों से आयात कीमत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, कई देश भारतीय बाजार में उत्पाद की आपूर्ति करते रहे हैं। तथापि, कोरिया से आयातों का हिस्सा 2017-18 से कुल आयातों का 50 प्रतिशत से अधिक था जो कोरियाई आयातों द्वारा प्रभावी स्थिति दर्शाता है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत है और इसीलिए केवल नियमावली के प्रावधान संगत हैं।

ड.1 विचाराधीन उत्पाद

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 40022000 के तहत वर्गीकृत "पॉलीबुटाडीन रबर" (जिसे पीबीआर भी कहा जाता है) है, एक सिंथेटिक रबर है जो मोनोमर 1, 3-बुटाडीन के पॉलीमरिजेशन से निर्मित पॉलीमर है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से टायरों के निर्माण में किया जाता है और पॉलीस्टीन तथा एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन स्टायरीन जैसे प्लास्टिक की यांत्रिक ताकत में सुधार के लिए एडिटिव के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है।
10. यह देखा जाता है कि यह उत्पाद पांच ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जिनमें उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक के आधार पर अंतर किया जा सकता है। इन ग्रेडों को नियोजनानियम, कोबाल्ट, निकिल, टाइटेनियम और लीथियम के रूप में अभिज्ञात किया जा सकता है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि वह दो ग्रेडों अर्थात् टाइटेनियम और लीथियम का उत्पादन नहीं करता। हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि नियोजनानियम ग्रेड को जांच के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने नियोजनानियम ग्रेड का उत्पादन और बिक्री नहीं की है और इस प्रकार नियोजनानियम ग्रेड को अलग करने के दावे में कोई औचित्य नहीं है।
11. यह भी देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व पाटनरोधी जांच में यही मुद्दा उठा जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था:

"12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीबीआर और आयातित पीबीआर की जांच करने पर प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों के बीच कोई वास्तविक अंतर सिद्ध नहीं कर पाए। विनिर्माण प्रक्रिया और प्रतिस्थापनीयता में समानता के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं।"

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पीबीआर के टाइटेनियम और लीथियम ग्रेडों को छोड़कर नियोजनानियम, कोबाल्ट और निकिल ग्रेडों के एचएस कोड 40022000 के तहत वर्गीकृत "पॉलीबुटाडीन रबर" के रूप में रखा गया है।

इ.2 घरेलू उद्योग

13. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में इस मुद्दे के संबंध में आवेदकों द्वारा अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अतिरिक्त अनुरोध नहीं किया गया है।
14. नियम 2(ख) द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली, 2007 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का अभिप्राय-

(i) भारत के सीमा क्षेत्र में प्रचालित होने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के समग्र रूप से उत्पादक; अथवा

(ii) वे उत्पादक जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के सामूहिक उत्पादन में उन सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात हो;

15. यह देखा जाता है कि आवेदक देश में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। अतः नियमावली के तहत आधार की अपेक्षा पूरी होती है और आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माना जाता है।

इ.3 जांच की अवधि

16. जांच की शुरुआत की सूचना में अधिसूचित किए गए अनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह एक रक्षोपाय जांच है, अतः विगत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक ने सबसे हाल की अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, होने के नाते सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

इ.4 गोपनीयता

17. नियमावली का नियम 6 सूचना की गोपनीयता से संबंधित है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर महानिदेशक ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। महानिदेशक ने सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराये।

इ.5 व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत सीमा शुल्क

18. व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (सीईपीए) के तहत रियायतों को ध्यान में रखते हुए पॉलीबुटाडीन रबर के आयातों पर सीमा शुल्क की दर निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सीमा शुल्क अधिसूचना	अधिसूचना की तारीख	दर
1	सं.- 152/ 2009-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2009	10.94%
2	सं.- 137/ 2010-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2010	9.38%
3	सं.- 123/ 2011-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2011	7.81%
4	सं.- 066/ 2012-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2012	6.25%
5	सं.- 054/ 2013-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2013	4.69%
6	सं.- 035/ 2014-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2014	3.13%
7	सं.- 060/ 2015-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2015	1.56%
8	सं.- 066/ 2016-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2016	0.00%

ड.6 सूचना का स्रोत

19. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। महानिदेशक ने अपेक्षित विश्लेषण के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य के परिकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड.7 कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयात

20. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 2(ग) में उल्लेख है:

"बढ़े हुए आयातों" में कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि शामिल है, भले ही पूर्ण संदर्भ में हों अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में;

21. उपर्युक्त नियमावली में यह जांच अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात पूर्ण दृष्टि से अथवा सापेक्ष दृष्टि से इतनी मात्राओं में बढ़े कि वे "बढ़े हुए आयात" बने। महानिदेशक ने पूर्ण दृष्टि से और भारत में आयातों के संबंध में, भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में आयातों की जांच की। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

i. कोरिया गणराज्य से पूर्ण दृष्टि के आयात

22. आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मात्रा मी. टन	प्रवृत्ति सूचकांक	सीमा शुल्क
1	2015-16	23,876	100	2.74%
2	2016-17	26,459	111	1.17%
3	2017-18	46,344	194	0.00%
4	2018-19	48,658	204	0.00%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	12,316	206	0.00%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	10,692	179	0.00%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	23,008	193	0.00%

23. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात इस अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं।

ii. भारत में कुल आयातों के संबंध में आयात

24. कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मी. टन में			आयातों में हिस्सा	
		कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कुल आयात	कोरिया गणराज्य	अन्य देश
1	2015-16	23,876	39,702	63,578	38%	62%
2	2016-17	26,459	45,247	71,706	37%	63%
3	2017-18	46,344	38,744	85,088	54%	46%
4	2018-19	48,658	41,976	90,634	54%	46%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	12,316	11,240	23,556	52%	48%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	10,692	9,281	19,973	54%	46%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	23,008	20,520	43,529	53%	47%

25. यह देखा जाता है कि कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा बढ़ती हुई प्रशुल्क रियायत से इस अवधि में बढ़ा जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। प्रशुल्क की पूर्ण समाप्ति से कोरियाई आयातों ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों में प्रमुख हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि जब कई अन्य देशों से आयात सूचित किए जा रहे हैं तो सामूहिक रूप से उनका हिस्सा अकेले कोरिया के हिस्से से कम है।

iii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि

26. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध सामानों के आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	विवरण	कोरिया आयात मी. टन	प्रवृत्ति उत्पादन मी. टन	प्रवृत्ति मांग मी. टन	के संबंध में आयात	
					उत्पादन %	खपत %
1	2015-16	23,876	100	100	21%	14%
2	2016-17	26,459	104	106	23%	14%
3	2017-18	46,344	101	112	41%	24%
4	2018-19	48,658	109	116	40%	24%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	12,316	116	117	38%	24%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	10,692	115	102	33%	24%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	23,008	115	109	36%	24%

27. यह देखा जाता है कि कोरिया से आयात शुल्क रियायत में वृद्धि से भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़े।
28. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि आयात कोरियाई निर्यातों को दी गई पूर्ण रियायतों से काफी बढ़े हैं।

ड.8 क्षति

29. गंभीर क्षति नियमावली के तहत निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

(च) **गंभीर क्षति** का अर्थ किसी घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि है; और

(छ) **"गंभीर क्षति के खतरे"** का अर्थ है कि वह गंभीर क्षति जो तथ्यों के आधार पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर स्पष्ट रूप से आसन्न हो।

30. इस प्रकार, आयातों में वृद्धि वह होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि करें।

31. नियमावली के नियम 7 में भी निम्नलिखित प्रावधान है:

महानिदेशक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा निर्धारित करेंगे, यथा:-

(क) महानिदेशक पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से मूल देश के सामान के आयातों में वृद्धि की दर तथा मात्रा, मूल के सामान के बढ़े हुए आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन को विशेष रूप से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुपरक एवं मात्रात्मक सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे; और

(ख) इस नियम के तहत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जांच वस्तुपरक साक्ष्य के आधार पर मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों तथा उसकी गंभीर क्षति अथवा खतरे के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी न दर्शाए और जब मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों तो वह क्षति मूल देश के सामानों के बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं होगी।

32. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध मानदंडों का मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अतः महानिदेशक ने वर्तमान मामले के तथ्यों और उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी अथवा अन्यथा के तथ्य की जांच की है। इस प्रकार, सभी सूचीबद्ध कारकों और किन्हीं अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन भी किया गया है। तदनुसार, गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में नियमों में उल्लिखित सभी कारकों तथा अन्य कारकों, जो गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है। इस प्रकार, गंभीर क्षति का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

क. पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से आयातों में वृद्धि

33. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

ख. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

34. क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	प्रवृत्ति क्षमता	प्रवृत्ति उत्पादन	क्षमता उपयोग	प्रवृत्ति घरेलू बिक्री	प्रवृत्ति निर्यात
		मी. टन	मी. टन	%	मी. टन	मी. टन
1	2015-16	100	100	95%	100	100
2	2016-17	100	104	99%	102	77
3	2017-18	100	101	96%	100	103
4	2018-19	100	109	104%	101	203
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	100	116	110%	99	266
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	100	115	109%	88	397
7	अप्रैल से सितंबर, 19	100	115	109%	93	331

35. यह देखा जाता है कि

- क. घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग में भी सुधार हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में पूर्व में उत्पादन के अनुसार बढ़ रही थी, परंतु पूर्ण शुल्क रियायत से घरेलू बिक्री पहले स्थिर हो गई है और फिर उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उसमें गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्री में तदनुसूची वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यात में वृद्धि घरेलू बाजार में उसके उत्पादन के लिए मांग न होने के कारण है क्योंकि वह आयात शुल्क की समाप्ति के बाद घरेलू बाजार में अपने पूरे उत्पादन की बिक्री नहीं कर पाया है।
- ग. घरेलू बिक्री उत्पादन में वृद्धि तथा देश में पर्याप्त मांग की मौजूदगी के बावजूद नहीं बढ़ी है।

ग. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

36. बाजार हिस्से का संचलन निम्नलिखित था:

क्रम सं.	विवरण	मांग में हिस्सा प्रतिशत			
		घरेलू उद्योग	अन्य देश	कोरियाई आयात	कुल
1	2015-16	63%	23%	14%	100%
2	2016-17	61%	25%	14%	100%
3	2017-18	56%	20%	24%	100%
4	2018-19	55%	21%	24%	100%

5	अप्रैल, 19 – जून, 19	54%	22%	24%	100%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	55%	21%	24%	100%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	54%	22%	24%	100%

37. यह देखा जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, कोरियाई आयातों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई।

घ. रोजगार एवं उत्पादकता

38. रोजगार एवं उत्पादकता संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन उत्पादकता	प्रति कर्मचारी उत्पादकता
		प्रवृत्ति सं.	प्रवृत्ति मी. टन/दिन	प्रवृत्ति मी. टन/सं.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	97	104	107
3	2017-18	92	102	111
4	2018-19	89	109	122
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	89	116	130
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	89	115	129
7	अप्रैल से सितंबर, 19	89	115	129

39. कर्मचारी की संख्या आयात शुल्क की तत्काल समाप्ति के बाद कम हुई है। तथापि, उत्पादकता के मानदंड के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई ह्रास नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता अन्य मानदंडों की संख्या पर निर्भर होती है और आयातों से सीधे ही संबद्ध नहीं है।

ड. मालसूची

40. मालसूची संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	विवरण	आरंभिक स्टॉक प्रवृत्ति (मी. टन)	अंतिम स्टॉक प्रवृत्ति (मी. टन)	औसत स्टॉक प्रवृत्ति (मी. टन)
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	55	138	82
3	2017-18	67	76	70
4	2018-19	37	50	41
5	तिमाही-1-2019-20	24	83	44
6	तिमाही-2-2019-20	40	136	72

41. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास पूर्व में उच्च स्तर की मालसूची थी। मालसूची के स्तर में मार्च, 2019 तक गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग में मालसूची उसके बाद एक बार फिर बढ़ी।

च. लाभ/हानि

42. लाभ संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	वर्ष	लाभ/(हानि)		आरओआई
		कुल प्रवृत्ति (लाख रु.)	प्रति यूनिट प्रवृत्ति (रु./मी. टन)	प्रवृत्ति
1	2015-16	-100	-100	-100
2	2016-17	-67	-65	-59
3	2017-18	-6	-6	-6
4	2018-19	-33	-33	-29
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	28	28	26
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	-49	-55	-44
7	अप्रैल से सितंबर, 19	-10	-22	-9

43. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद में काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वह उस समय विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व में लाभ में था जब उत्पाद पर कोई शुल्क रियायतें नहीं थीं। तथापि, सीईपीए के तहत दी गई शुल्क रियायतों से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी समाप्त हो गई और घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानियां हो रही हैं। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के मद्देनजर प्राधिकारी ने लागू सीमा शुल्क के साथ 2007-08 से आवेदन पत्र में दी गई लाभ/हानि संबंधी सूचना पर विचार किया है। यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग पूर्व में उस समय लाभ में था जब कोई रियायत नहीं थी या कम रियायत थी तथा घरेलू उद्योग को अब उस समय वित्तीय हानियां हो रही हैं जब कोरियाई आयातों को पूर्ण रियायतें हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	सीमा शुल्क	लाभ/हानि
	%	प्रवृत्ति रु./मी. टन
2007-08	10.00%	100
2008-09	10.00%	151
2009-10	10.00%	98
2010-11	6.88%	216
2011-12	5.00%	41
2012-13	4.38%	159
2013-14	1.88%	43
2014-15	0.00%	-52
2015-16	0.00%	-60
2016-17	0.00%	-39
2017-18	0.00%	-3
2018-19	0.00%	-20
अप्रैल, 19 – जून, 19	0.00%	17
जुलाई, 19 – सितंबर, 19	0.00%	-33
अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	0.00%	-7

छ. कीमत कटौती

44. यह जांच की गई थी कि क्या कोरिया से आयात बाजार में उत्पाद की कीमतें निर्धारित कर रहे थे। इस प्रयोजन के लिए, कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से विभिन्न देशों से आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की गई थी। महानिदेशक ने यह भी जांच की कि क्या कोरियाई आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। कोरियाई

आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास के संदर्भ में की गई है।

क्रम सं.	वर्ष	पहुँच कीमत				घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत
		कोरिया गणराज्य	आसियान देश	जापान	अन्य देश	प्रवृत्ति
		रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन
1	2015-16	89,939	87,099	83,903	89,590	100
2	2016-17	1,14,176	1,21,863	99,444	1,08,450	145
3	2017-18	1,28,169	1,32,194	1,65,028	1,35,062	141
4	2018-19	1,33,118	1,34,850	1,35,202	1,36,999	150
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	1,08,887	1,09,597	1,22,086	1,20,920	124
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	1,08,909	1,10,581	1,16,364	1,16,611	123
7	अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	1,08,897	1,10,024	1,18,620	1,18,921	124

क्रम सं.	वर्ष	पहुँच कीमत – सूचीबद्ध				घरेलू बिक्री कीमत – सूचीबद्ध प्रवृत्ति
		कोरिया गणराज्य	आसियान देश	जापान	अन्य देश	
1	2015-16	100	97	93	100	100
2	2016-17	100	107	87	95	145
3	2017-18	100	103	129	105	141
4	2018-19	100	101	102	103	150
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	100	101	112	111	124
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	100	102	107	107	123
7	अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	100	101	109	109	124

45. यह देखा जाता है कि जबकि पूर्व में शेष विश्व से आयात कीमत वे थीं, जो 2017-18 से कोरिया से आयात कीमत से कम अथवा बराबर थी, जब कोरियाई निर्यातों को पूर्ण शुल्क रियायत लाभ प्राप्त थे, कोरियाई कीमतें ही शेष विश्व से आयात कीमत से कम थीं। इसके अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही हैं जो इस प्रकार सिद्ध करती हैं कि घरेलू उद्योग कोरिया गणराज्य से आयात कीमतों के साथ अपनी कीमतें निर्धारित करने के लिए मजबूर हुआ है।
46. कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जो घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

क्रम सं.	वर्ष	एनएसआर	पहुँच कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		प्रवृत्ति रु./मी. टन			%
1	2015-16	100	89,939	*****	2.5-12.5%
2	2016-17	145	1,14,176	*****	15-25%
3	2017-18	141	1,28,169	*****	2.5-12.5%
4	2018-19	150	1,33,118	*****	2.5-12.5%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	124	1,08,887	*****	5-15%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	123	1,08,909	*****	5-15%
7	अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	124	1,08,897	*****	5-15%

47. निम्नलिखित तालिका कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत की तुलना दर्शाती है :

क्रम सं.	वर्ष	बिक्री की लागत	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत – कोरिया गणराज्य
		प्रवृत्ति रु./मी. टन	प्रवृत्ति रु./मी. टन	रु./मी. टन
1	2015-16	100	100	89,939
2	2016-17	135	145	1,14,176
3	2017-18	122	141	1,28,169
4	2018-19	134	150	1,33,118
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	102	124	1,08,887
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	115	123	1,08,909
7	अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	108	124	1,08,897

48. यह देखा जाता है कि कोरियाई उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ही कम नहीं थीं, बल्कि वर्ष 2017-18 और अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही को छोड़कर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम थीं।

ड. क्षति संबंधी निष्कर्ष

49. उपर्युक्त विश्लेषण से इस प्रकार अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में सकल आयातों के संबंध में, भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कोरिया गणराज्य से आयातों में काफी उछाल के परिणामस्वरूप और चूंकि शुल्क रियायत बढ़ गई थी, अतः घरेलू उद्योग को स्थिर बिक्री, गिरते हुए बाजार हिस्से, काफी वित्तीय हानियों और निवेश पर नकारात्मक आय के संदर्भ में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में, घरेलू उत्पादक के निष्पादन पर विचार करते हुए, यह आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है जिससे कोरिया से कम कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े।

छ. कारणात्मक संपर्क

50. ऊपर दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। यह जांच की गई थी कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों तथा परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के मद्देनजर कि महानिदेशक को इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या दावा की गई क्षति शुल्क रियायतों के कारण है अथवा किन्हीं अन्य कारकों से है, महानिदेशक ने उस अवधि सहित मंदी अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी विचार किया जब शुल्क रियायत नहीं थी। इस निमित्त संगत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र में निहित है जिसे हितबद्ध पक्षकार आवेदन पत्र के सार्वजनिक रूपांतर के माध्यम से भी देख सकते हैं।

- क. यह जांच की गई थी कि क्या किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। महानिदेशक ने विभिन्न जांच मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए मानदंडों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को सूचित क्षति इस समय प्रचालित हो रहे अन्य कारकों की संभावित मौजूदगी के कारण नहीं है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कोरियाई आयातों को प्रशुल्क रियायतों में वृद्धि तथा उसके सीमा शुल्क की समाप्ति से काफी वृद्धि हुई है।
- ग. पूर्ण शुल्क रियायतों से कोरियाई आयातों की पहुँच कीमत शेष विश्व के आयातों की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कोरियाई कीमतें भी सबसे कम होने के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतें निर्धारित कर रही थीं।

घ. यद्यपि, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए आयातों के अनुसार नहीं बढ़ी है। स्थिर हो रही घरेलू बिक्री और कम अनुकूल कीमतों पर बढ़ते हुए निर्यात भारत में आयातों में वृद्धि के परिणाम हैं।

51. इस प्रकार, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए कोरियाई आयातों के कारण हुई है और कोरिया से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है।

ज. महत्वपूर्ण परिस्थिति

52. द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 8 में यह प्रावधान है कि महानिदेशक शीघ्रता से जांच करेंगे और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जहां यह स्पष्ट साक्ष्य हो कि बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा वे गंभीर क्षति पैदा करने का खतरा पैदा कर रहे हैं और जहां अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाने में विलंब घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाएगा जो ठीक करना कठिन होगा, महानिदेशक मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के संबंध में प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड करें। महानिदेशक मानते हैं कि निम्नलिखित तथ्य अंतरिम रक्षोपाय लगाए जाने की आवश्यकता वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों की मौजूदगी सिद्ध करते हैं:

- क. शुल्क रियायतें 2017-18 में पूरी मात्रा तक बढ़ने से कोरिया गणराज्य से उत्पाद के आयातों का हिस्सा कुल आयातों में 2007-08 में 16 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 37 प्रतिशत और 2017-18 में 54 प्रतिशत तक हो गया और उसके बाद उसी उच्च स्तर पर बना रहा है।
- ख. वर्तमान अवधि के दौरान काफी शुल्क रियायतों से घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां होती रही हैं जिससे निवेश पर नकारात्मक आय हुई।
- ग. यद्यपि, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर पाया, तथापि, विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद वह अपनी घरेलू बिक्री में आनुपातिक वृद्धि करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई है।
- ङ. परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री में सबसे हाल की अवधि (जुलाई-सितंबर, 2019 की अवधि) में और काफी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी इस अवधि में काफी प्रभावित हुई है। जुलाई-सितंबर, 2019 में बिक्री की मात्रा 2016-17 में बेची गई मात्रा से 14 प्रतिशत कम थी।
- च. घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर हो गया है।
53. यह नोट किया जाता है कि प्रस्तुत कारक महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं और भारतीय उद्योग के समग्र निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं जो अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने का औचित्य बनाते हैं।

झ. समायोजन योजना

54. आवेदक ने जांच प्रक्रिया के दौरान समायोजन योजनाओं के ब्यौरे दिए हैं। आवेदक ने बताया है कि वह कई कारणों से लागतें कम करने के निमित्त निर्देशित उपाय करेंगे। आवेदक ने उत्प्रेरक एवं रसायन लागत कमी, परिवर्तन लागत कमी, प्रसंस्करण दक्षता में सुधार, खपत मानदंडों में सुधार, परिवहन लागत में कमी, स्टॉक के आमूल-चूल परिवर्तन में सुधार आदि पर निर्देशित कार्रवाई योजना अभिज्ञात की है। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक ने आयात प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए एक समायोजन योजना तैयार की है।

ञ. निष्कर्ष एवं सिफारिश

55. उपर्युक्त प्राथमिक जांच के आधार पर, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है। यह माना जाता है कि महत्वपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान हैं जहां रक्षोपाय लगाने में विलंब से घरेलू उत्पादकों को अपूरणीय क्षति होगी। द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने के संबंध में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 में निम्नलिखित उल्लेख है:

(1) महानिदेशक के प्राथमिक जांच परिणामों के आधार पर केंद्र सरकार-

- (क) व्यापार करार के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की किसी दर को और कम करने को रद्द कर सकती है; अथवा
- (ख) निम्नलिखित से कमतर से अनधिक के स्तर तक मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर बढ़ा सकती है:
 - (i) सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र में उस समय प्रभाव में मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर लागू की हो जब द्विपक्षीय रक्षोपाय किया गया हो; और
 - (ii) सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र में व्यापार करार की लागू प्रविष्ट तारीख से तत्काल पूर्व के दिवस को प्रभाव में मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर लागू की हो।

(2) उप नियम (1) के तहत द्विपक्षीय रक्षोपाय उन्हें लगाए जाने की तारीख से 200 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए ही लागू रहेंगे।

56. उपर्युक्त की जांच करने के बाद, भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 के अनुसार, अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय की सिफारिश करना उपयुक्त माना जाता है। तदनुसार, अंतिम निर्धारण होने तक प्राधिकारी अनंतिम रूप से कोरिया गणराज्य के मूल के संबद्ध सामानों के आयातों पर सीमा शुल्क की दर द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू होने की तारीख को संबद्ध सामानों पर एमएफएन शुल्क के स्तर तक अथवा व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व के दिवस को संबद्ध सामानों पर एमएफएन शुल्क, जो भी कम हो, बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।
57. उपर्युक्तानुसार, उपर्युक्त उत्पाद के आयात पर अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय की 200 (दो सौ दिन) दिनों की अवधि के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव है।

ट. आगे की प्रक्रिया

58. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- क. महानिदेशक प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणाम पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं। उनसे प्राप्त टिप्पणियों की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी।
- ख. महानिदेशक सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संगत उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी। मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- ग. महानिदेशक आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन करेंगे।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2020

PRELIMINARY FINDINGS**Case No: SG-07/2019**

Subject: Preliminary findings in Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Polybutadiene Rubber” from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/7/2019-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Korea (hereinafter referred to as “CEPA”) and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the “Rules” or “Bilateral Safeguard Rules”) thereof, M/s Reliance Industries Limited (herein after referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the “Director General” or “Authority”) in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of bilateral safeguard investigation concerning increased imports of Polybutadiene Rubber (hereinafter referred to as the “product under consideration” or “subject goods”) from Korea RP (herein after referred to as “subject country”)
2. The Director General, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued notification number SG-07/2019 dated 7th November 2019, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with the Rules.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation-
 - a. The Director General sent a copy of the initiation notification dated 7th November, 2019 to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules.
 - b. Copy of the non-confidential version of the application filed by the Applicant was made available to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules.
 - c. The Director General forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers / exporters in the subject country and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules:
 - i. Kumho Petrochemicals Ltd.
 - ii. LG Chem Ltd.
 - d. In response to the questionnaire issued, both the producers/exporters filed exporter’s questionnaire responses.
 - e. The Director General sent Importer Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 5(4) of the Rules:
 - i. J K Tyres Industries Ltd.
 - ii. Apollo Tyres Ltd.
 - iii. MRF Ltd.
 - iv. CEAT Limited

- v. Birla Tyres
- vi. Balkrishna Industries Ltd.
- vii. Goodyear India Limited
- viii. Continental India Ltd.
- ix. Yokohama India Private Limited
- x. Metro Tires Limited
- xi. Ralson India Limited
- xii. Treads direct Limited
- xiii. Indag Rubbers Limited

f. In response to the questionnaire issued, the following importers have filed importer questionnaire response:

- i. TVS Srichakra Limited
- ii. Apollo Tyres Limited
- iii. MRF Limited
- iv. CEAT Limited

g. The Authority also sent questionnaire to the domestic industry. The domestic industry filed its questionnaire response.

h. The following interested parties filed submissions responding to the initiation notification:

- i. Korea Petrochemical Industry Association
- ii. Korean Government
- iii. All India Rubbers Industries Association

i. The Director General made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

j. The submissions made by the interested parties so far, wherever found relevant, have been considered while issuing these preliminary findings.

C. SUBMISSIONS MADE BY THE APPLICANT

4. The submissions made by the Applicant are as follows: -

- a. There are 5 types of Polybutadiene Rubber out of which Titanium and Lithium grades are not made by the domestic industry. Titanium grade of Polybutadiene Rubber has inferior quality and has become obsolete. Lithium Grade is used in plastic modification. The scope of product under consideration therefore does not cover these two grades.
- b. The period selected in the application is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports and injury thereof.
- c. The period under consideration should include period of no concessions, tariff reductions and post-tariff elimination to ascertain whether the injury to the domestic industry is as a result of duty concessions.
- d. The imports of the product under consideration show significant increase over the period with increase in duty concession.
- e. In the last 12 years, the imports have increased by around 1093 times due to the concessions given under CEPA. Further, with custom duty becoming zero, the imports have doubled in the last 3 years.
- f. The demand for the subject goods has increased over the period with a slight decline in 2008-09.
- g. The share of the subject imports in the demand has increased from 4% to 24% while that of the domestic industry has declined from 73% to 55%.
- h. The Korean producers are price setters in the market and the domestic industry and other country imports are forced to follow the pattern of the pricing set by them.

- i. The domestic industry is unable to increase the selling prices to the extent of the cost of sales. The present low prices are only because of the low prices of the subject country imports.
- j. The industry has been suffering financial losses since 2014-15.
- k. The adverse volume impact on the performance of the domestic industry can be seen from the fact that the industry has not been able to sell the product in the domestic market and been forced to focus on less profitable exports.
- l. The inventory of the domestic industry has risen.
- m. The volume of imports has increased more in the quarter 1 and quarter 2 of the 2019-20.
- n. With regard to adjustment plans, the domestic industry has submitted that it is taking measures to reduce costs. The domestic industry has given an adjustment plan which includes action on catalyst & chemicals cost reduction, conversion cost reduction, improvement in process efficiency, improvement in consumption norms, reduction in transportation costs, improvement in turnaround of stocks, etc. Since domestic industry competes with imports on the basis of landed price of imports at the premises of the customer, the company shall become competitive vis-à-vis Korean imports in a period of four years.

D. SUBMISSIONS MADE BY OTHER INTERESTED PARTIES

D.1 Korea Petrochemical Industry Association

5. The submissions made by the Korea Petrochemical Industry Association are as follows:
 - a. In the Anti-Dumping investigation on the subject imports, the Authority had concluded that the injury caused was not due to dumping. Therefore, with improved performance, how can serious injury be caused now?
 - b. The non-confidential version of the application fails to meet the standards laid down in Trade notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which is issued by the Directorate General of Trade Remedies and is applicable for all trade remedy investigations. The application does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein.
 - c. The Applicant must share revised data based on the period as determined by the Director General i.e., April 2015 to June 2019.
 - d. Rule 4(2)(b) of the Bilateral Safeguard Rules requires the petitioner to compulsorily file adjustment plan. In the absence of adjustment plan, duty imposition was not recommended by the Director General in Phthalic Anhydride (PAN), Cold Rolled Flat Products, Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium and Flexible Slabstock Polyol.
 - e. Article XIX of GATT 1994 requires unforeseen developments which could have led to increase in imports which the Applicant has failed to address in the petition. Further, increase in imports cannot be held as unforeseen developments as held by panel in Argentina – Preserved Peaches case.
 - f. The domestic industry does not have the ability to meet the domestic demand. The imports from Korea RP have increased with the increase in demand.
 - g. The requirements of the Article 2.23 of the CEPA have not been met as: -
 - i. The alleged increase in imports is not a result of the reduction or elimination of the duties under the Korea-India CEPA.
 - ii. There has been no recent, sudden, sharp, and significant increase in Korean imports of PBR into India
 - iii. Any alleged increased imports of PBR have not caused serious injury or threat thereof; and
 - iv. Korean Imports of PBR have not alone constituted a substantial cause of serious injury to the domestic industry
 - h. There is no serious injury or threat of injury as defined by the section 8B(6)(c) and (d) of the Act and the Article 4.1 (a) of Agreement on Safeguards. In fact the performance of the domestic industry has improved.
 - i. Non-Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium, Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series, Bare Elastomeric Filament Yarn are some of the past investigations, where the Director General had terminated the investigation as the performance of industry had improved.

- j. The applicant has transferred the raw material at a cost higher than the actual cost, which has resulted in increase in claimed cost of the subject goods.
- k. In compliance with the Article 4.2(b) of the agreement and Rule 7 of the rules, the Director General is required to examine causal link between the increase in imports and injury and do the non-attribution analysis.
- l. The performance of the domestic industry has improved with the reduction in the custom duties.
- m. The domestic industry does not produce Neodymium Grade which has major imports from Korea RP. Even if produced, the product won't meet or pass industrial users quality certification. This product is limited in use for end-user, especially global tyre manufacturers.
- n. The rate of increase in imports from ASEAN countries is higher than rate of imports from the subject country.
- o. Since the Applicant is the only producer of the subject goods, the imposition of the duty will not be in public interest. The Applicant would create dominant position for itself in the market and create barriers for new entrants.
- p. The prices of the product are set in accordance with the prices of butadiene, therefore, the fall in prices cannot be attributed to import price.

D.2 Submissions made by the Korean Government

6. The submissions made by the Korean Government are as follows-

- a. The current circumstances of the Indian domestic industry do not qualify for critical circumstances requiring imposition of provisional safeguard measures as per Article 2.24 of Korea – India CEPA.
- b. The investigation must be terminated on the ground that Applicant has not submitted any adjustment plan as is mandatorily required to be provided under Article 2.23 (g) of the Korea – India CEPA and Rule 4(2) b of the Rules.
- c. The data provided by the Applicant in the petition does not contain any data for period April - June 2019.
- d. The market share of the domestic industry is not growing due to the inability of the domestic industry to provide a reasonable alternative to the imported goods and its low capacity to fulfil the demand.
- e. The presentation of data from 2007-08 for indexation has led to inaccurate representation of developments in the domestic market.
- f. The Applicants have claimed excessive confidentiality in their Application as the data which was available in the ADD Final Finding of the subject goods has not been disclosed.
- g. The requirements of the Article 2.22 of the CEPA have not been met and therefore the measures cannot be applied.
- h. The major reason contributing towards the increase in the imports should be the reduction or elimination of tariffs on that article pursuant to the CEPA. However, in the present investigation the same is missing.
- i. There has been a consistent decline in the rate of custom duty since 2010 but the imports from subject country did not increase at the same rate. Further, the increase in imports is due to increase in demand.
- j. Bare Elastomeric Filament, Flexible Slabstock Polyol, White/Yellow Phosphorus are some of the investigations where DGTR has not recommended safeguards duty on the grounds of demand supply gap.
- k. The imports from other countries have increased at a faster rate as compared to imports from Korea RP.
- l. As per Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, there must be a reasoned and adequate explanation which demonstrates the connection between the reduction of the duty and the alleged increase in imports. Director General should identify and provide a reasoned explanation and demonstration of the same.
- m. There is no sudden, significant or sharp increase in the imports as per the language of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards.

- n. The economic performance of the domestic industry has seen a positive growth. All relevant parameters such as market share, production, productivity, capacity utilization, sales, profits and losses and employment have shown a positive trend.
- o. Korea's recent export of polybutadiene rubber to India from January to September 2019 has decreased by 13%.

D.3 Submissions made by the All India Rubbers Industries Association

7. The submissions made by All India Rubbers Industries Association are as follow-

- a. The performance of the domestic industry has improved. In the recent anti-dumping investigation on the subject goods, the Authority had concluded that the injury was not due to dumping. Therefore, the Applicant could not have suffered injury in the current investigation in spite of improved performance.
- b. The Applicant has not brought forward sufficient evidence to prove the conditions for initiation of the bilateral safeguard investigation. Conditions laid down in Article 2.22 are not satisfied.
- c. The Applicant has made false statements coupled with inaccurate information.
- d. The application does not allow a reasonable understanding of the allegations as it fails to meet the standards laid down in Trade notice no. 10/2018. The trade notice issued by DGTR is applicable for all trade remedy investigations.
- e. The Applicant has not provided the adjustment plan as required under Rule 4(2)(b) of the Bilateral Safeguard. In the past the Director General had not recommended safeguard measures in Phthalic Anhydride (PAN), Cold Rolled Flat Products, Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium and Flexible Slabstock Polyol where the adjustment plan was not submitted.
- f. Mere increase in the volume of imports cannot be seen as unforeseen developments. The Director General was required to examine the same.
- g. There is absence of serious injury or threat of serious injury as per Section 8B(6)(c) and (d) of the Act. Instead, the performance of the domestic industry has improved.
- h. The Director General had not recommended duty in Non-Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium, Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series, Bare Elastomeric Filament Yarn where the performance of industry had improved.
- i. The increased cost is due to the Applicant transferring the raw material at costs higher than the actual cost.
- j. There is absence of causal link in the investigation. The Authority should examine causal link and perform non attribution analysis.
- k. There has been an increase in imports from ASEAN countries sharper as compared to subject imports.
- l. The domestic industry does not have the ability to meet the domestic demand. The imports from Korea RP have increased with the increase in demand.
- m. The imposition of duty will allow the Applicant to create dominant position for itself in the market and create barriers for new entrants.

E. EXAMINATION BY THE DIRECTOR GENERAL

- 8. The information made available by the interested parties in their submissions, have been considered by the Authority for the purpose of the present determination. The Authority has examined views of interested parties and has appropriately considered the same for the purpose of the preliminary findings.
 - a. As regards imports from other ASEAN countries, it is seen that the volume of imports in absolute terms from individual countries is low and landed price of imports from these countries is higher than landed price of imports from Korea.
 - b. The interested parties contended that the volume of imports has not increased with increase in tariff concession. The Authority, therefore, examined imports of the product before tariff concession, during the period of tariff concession and post-elimination of tariff. Relevant information is contained in the application. It is seen that as the concession increased, the volume of imports from Korea increased. It is evident that with the increase in tariff concession, the Korean imports increased.
 - c. As regards reference to anti-dumping case, it is noted that the Authority had concluded that there was injury to the domestic industry but it was not on account of dumped imports. In fact, the absence of

dumping was largely attributable to the tariff concessions granted to imports from Korea RP under India-Korea CEPA.

- d. As regard the contention that the price of product is set by raw material price, it is noted that this does not imply that the duty concession cannot cause injury to the domestic industry.
- e. With regard to the contention that the Authority must find injury solely due to present imports, it is noted that the rule does not state that the sole cause of injury to the domestic industry should be subject imports. Further, in view of the arguments of the parties, Authority examined financial situation of the domestic industry over a longer period including pre-concession period. It is seen that the financial situation of domestic industry has materially deteriorated as the tariff concession increased. Whereas the domestic industry was earlier earning profits when the product was not subject to tariff concessions, the domestic industry is now suffering financial losses with the tariff concessions granted to Korean exports.
- f. As regards the issue raised by some interested parties about the domestic industry not increasing capacities with rising demand, it is noted that the present petition merely seeks redressal of the adverse price effect on the domestic industry on account of tariff concessions.
- g. As regards adjustment plan, the Authority notes that the domestic industry has given an adjustment plan post-initiation of investigation.
- h. The Authority notes that the application contains data for the period April, 2007 to March, 2019. Further, while responding to initiation, the applicant has provided data for the period up to Sept, 2019. Thus, the interested parties have access to the relevant information and an opportunity to comment on the information for the period from April, 2007 to Sept., 2019. The Authority has considered the period from April, 2015 to Sept, 2019 for the purpose of examining increased imports and serious injury to the domestic industry. However, since the interested parties have contended that the Authority is required to consider whether the increase in import is as a result of tariff concessions under the Agreement and are consequently causing injury, the Authority has suitably referenced the data for longer period i.e. since April, 2007 as contained in the petition.
- i. The Authority notes that the present investigation is a bilateral safeguard investigation initiated under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 read with India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Authority has examined whether increased imports are as a result of tariff concessions under the agreement. For this purpose, the Authority has considered imports of the product from April, 2007 to Sep., 2019. It is seen that volume of imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption as the tariff concessions increased.
- j. As regards the contention that imports have increased due to demand supply gap, the Authority notes that demand supply gap may justify imports per-se. However, landed price from imports from Korea is lower than not only the selling price of domestic industry but also import price from several countries. Further, a number of countries have been supplying the product in Indian market. However, share of imports from Korea was more than 50% of total imports from 2017-18 showing dominant position gained by Korean imports.

The Authority notes that the present investigation is under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement and therefore only provisions of the Rules are relevant.

E.1 Product under consideration

9. The product under consideration in the present investigation is "Polybutadiene Rubber" classified under HS Code 40022000. Polybutadiene Rubber (also referred to as PBR) is a synthetic rubber that is a polymer formed from the polymerization of the monomer 1,3-butadiene. It is used in the manufacture of tyres mainly and is also used as an additive to improve the mechanical strength of plastics such as polystyrene and acrylonitrile butadiene styrene.
10. It is seen that the product is produced in 5 grades which can be differentiated on the basis of the catalyst used in production. The grades may be identified as: Neodymium, Cobalt, Nickel, Titanium and Lithium. The Applicant has stated that it does not produce two grades, i.e., Titanium and Lithium. With regards to the claim of the interested parties that Neodymium grade should be excluded from the scope of investigation, it is noted that the domestic industry has produced and sold neodymium grade and thus there is no merit in the claim for exclusion of Neodymium grade.
11. It is also seen that in the previous anti-dumping investigation on the product under consideration, the same issue arose where the Designated Authority concluded as follows:

“ 12. On examination of the PBR produced by the domestic industry and imported PBR, the Authority did not find any material difference between the subject goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject countries. It is also noted that the interested parties could not establish any material difference between the subject goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject countries. In view of the similarity in manufacturing process and substitutability, the Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the goods imported from the subject countries.”

12. On the basis of information on record, the scope of product under consideration has been kept as “Polybutadiene Rubber” classified under HS Code 40022000 of Neodymium, Cobalt and Nickel grades, excluding titanium and lithium grades of PBR.

E.2 Domestic industry

13. It is noted that no additional submission has been made either by the Applicant or the interested parties on this issue in the present investigation.
14. The Rule 2(b) of Bilateral Safeguard Measures Rules, 2017 states as follows: -
- “domestic industry” means the producers -*
- (i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or*
- (ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;*

15. It is seen that the Applicant is the only producer of the subject goods in the country. Therefore, the requirement of standing under the Rules is satisfied and the Applicant is considered as domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules.

E.3 Period of investigation

16. The period considered for the purposes of present investigation, as notified in the notice of initiation, is from April, 2015 to June, 2019. Further, since this is a safeguard investigation, considering the past practice, the Director General has considered the data for the period up to Sept., 2019, being the most recent period for which the data is available.

E.4 Confidentiality

17. Rule 6 of the Rules deals with confidentiality of information. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Director General has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Director General made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties available to all interested parties for inspection through public file.

E.5 Customs Duty under Comprehensive Economic Partnership Agreement

18. The rate of custom duty on the imports of Polybutadiene Rubber after considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is as follows: -

S.No.	Custom Notification	Date of Notification	Rate
1	No.- 152/ 2009-Customs	31st Dec 2009	10.94%
2	No.- 137/ 2010-Customs	31st Dec 2010	9.38%
3	No.- 123/ 2011-Customs	31st Dec 2011	7.81%
4	No.- 066/ 2012-Customs	31st Dec 2012	6.25%
5	No.- 054/ 2013-Customs	31st Dec 2013	4.69%
6	No.- 035/ 2014-Customs	31st Dec 2014	3.13%
7	No.- 060/ 2015-Customs	31st Dec 2015	1.56%
8	No.- 066/ 2016-Customs	31st Dec 2016	0.00%

E.6 Source of information

19. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports for the required analysis.

E.7 Increased imports from Korea RP

20. Rule 2 (c) of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states:

"increased imports" includes increase in imports from the Republic of Korea whether in absolute terms or relative to domestic production;

21. The said Rules require an examination whether imports of the PUC increased in such quantities in absolute or relative terms so as to constitute "increased imports". The Director General examined the imports, in both absolute terms and in relation to imports into India, production and consumption in India. Analysis of increased imports of the product under consideration has been conducted having regard to the said Rules.

i. Imports from Korea RP in absolute terms:

22. The movement of imports is shown in the table below:

S.No.	Year	Import volume	Trend	Customs duty
		MT	Index	
1	2015-16	23,876	100	2.74%
2	2016-17	26,459	111	1.17%
3	2017-18	46,344	194	0.00%
4	2018-19	48,658	204	0.00%
5	Apr'19-Jun'19	12,316	206	0.00%
6	Jul'19-Sep'19	10,692	179	0.00%
7	April to Sept.,19	23,008	193	0.00%

23. It is seen that imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms over the period.

ii. Imports in relation to total imports in India

24. The share of imports of subject goods from Korea RP and other countries is shown in the table below:

Sl.No.	Year	Imports in MT			Share in imports	
		Korea RP	Other countries	Total imports	Korea RP	Other countries
1	2015-16	23,876	39,702	63,578	38%	62%
2	2016-17	26,459	45,247	71,706	37%	63%
3	2017-18	46,344	38,744	85,088	54%	46%
4	2018-19	48,658	41,976	90,634	54%	46%
5	Apr'19-Jun'19	12,316	11,240	23,556	52%	48%
6	Jul'19-Sep'19	10,692	9,281	19,973	54%	46%
5	April to Sept.,19	23,008	20,520	43,529	53%	47%

25. It is seen that share of imports of the product under consideration from Korea increased over the period with the increasing tariff concession whereas the share of other countries declined. With total elimination of tariff, Korean imports have started commanding majority share in imports of the subject goods into India.

Even when imports are being reported from a number of other countries, their share collectively is lower than the share of Korea alone.

iii. **Increase in imports in relation to production and consumption in India**

26. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

S.No.	Particulars	Korea imports	Production	Demand	Imports in relation to	
					Production	Consumption
		MT	Trend MT	Trend MT	%	%
1	2015-16	23,876	100	100	21%	14%
2	2016-17	26,459	104	106	23%	14%
3	2017-18	46,344	101	112	41%	24%
4	2018-19	48,658	109	116	40%	24%
5	Apr'19-Jun'19	12,316	116	117	38%	24%
6	Jul'19-Sep'19	10,692	115	102	33%	24%
5	April to Sept.,19	23,008	115	109	36%	24%

27. It is seen that imports from Korea increased significantly in relation to production and consumption in India with increase in duty concession.

28. As noted above, the imports of subject goods have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. It is also seen that the imports increased significantly with the full concessions given to the Korean exports.

E.8 Injury

29. Serious Injury is defined as follows under the Rules:

(f) *serious injury means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and*

(g) *"threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent.*

30. Thus, increase in imports should be such which causes a significant overall impairment in the position of a domestic industry.

31. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely: -

(a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and

(b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods.

32. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Director General has therefore examined the fact of presence or otherwise of serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. Thus, in addition to the technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, the overall position of the industry in light of relevant factors having a bearing on the situation of that industry has also been evaluated,. Accordingly, in analyzing serious injury, all factors mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury, have been considered. The determination of serious injury thus is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

a. **Increase in imports in absolute and relative terms**

33. As noted above, imports of subject goods have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.

b. Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales

34. The details of capacity, capacity utilization, domestic sales and export sales are as follows-

S.No.	Years	Capacity	Production	Capacity Utilisation	Domestic sales	Export
		Trend MT	Trend MT	%	Trend MT	Trend MT
1	2015-16	100	100	95%	100	100
2	2016-17	100	104	99%	102	77
3	2017-18	100	101	96%	100	103
4	2018-19	100	109	104%	101	203
5	Apr'19-Jun'19	100	116	110%	99	266
6	Jul'19-Sep'19	100	115	109%	88	397
7	Apr-Sept.,19	100	115	109%	93	331

35. It is seen that

- the production of the domestic industry has increased over the injury period. Consequently, the capacity utilisation has also improved;
- The domestic sales of the domestic industry were increasing in line with the production earlier but with full duty concession, the domestic sales have stagnated earlier and then declined despite increase in production. Further, the domestic industry has made corresponding increase in its export sales. The domestic industry has contended that the increase in exports is on account of absence of demand for its product in the domestic market, as it has not been able to sell its entire production in the domestic market post-elimination of import duty.
- the domestic sales have not increased in line with increase in production and despite existence of sufficient demand in the country.

c. Market share of the domestic industry

36. The movement of market share is as follows:

S.No.	Particulars	Share in Demand%			
		Domestic industry	Other Countries	Korean imports	Total
1	2015-16	63%	23%	14%	100%
2	2016-17	61%	25%	14%	100%
3	2017-18	56%	20%	24%	100%
4	2018-19	55%	21%	24%	100%
5	Apr'19-Jun'19	54%	22%	24%	100%
6	Jul'19-Sep'19	55%	21%	24%	100%
7	April to Sept.,19	54%	22%	24%	100%

37. It is seen that whereas market share of domestic industry declined, the share of Korean imports increased significantly.

d. Employment and Productivity

38. The data on employment and productivity is as follows-

S.No.	Year	No .of Employees	Productivity per day	Productivity per employee
		Trend Nos.	Trend MT/Day	Trend MT/Nos.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	97	104	107
3	2017-18	92	102	111
4	2018-19	89	109	122
5	Apr'19-Jun'19	89	116	130

6	Jul'19-Sep'19	89	115	129
7	April to Sept.,19	89	115	129

39. The number of employees have reduced immediately after elimination of import duty. However, there is no deterioration in performance of the domestic industry on the criterion of productivity. The petitioner has claimed that employee strength and productivity are dependent on number of other parameters and are not directly linked to imports.

e. Inventory

40. The data on inventory shows as follows-

S.No.	Particulars	Opening stock Trend (MT)	Closing stock Trend (MT)	Average stock Trend (MT)
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	55	138	82
3	2017-18	67	76	70
4	2018-19	37	50	41
5	Q1-2019-20	24	83	44
6	Q2-2019-20	40	136	72

41. It is seen that the domestic industry was earlier holding high level of inventories. The level of inventories declined till March, 2019. However, inventories with the domestic industry increased once again thereafter.

f. Profit/loss

42. The data on profits shows as follows-

S.No.	Year	Profit/(loss)		ROI
		Total Trend (Rs. lacs)	Trend Per unit (Rs./MT)	Trend %
1	2015-16	-100	-100	-100
2	2016-17	-67	-65	-59
3	2017-18	-6	-6	-6
4	2018-19	-33	-33	-29
5	Apr'19-Jun'19	28	28	26
6	Jul'19-Sep'19	-49	-55	-44
7	April to Sept.,19	-10	-22	-9

43. It is seen that the domestic industry is suffering significant financial losses in the product under consideration. The domestic industry submitted that it was earlier in profits in respect of the product under consideration when the product was not having duty concessions. However, with the duty concessions given under CEPA, the profitability of the domestic industry got eroded significantly and the domestic industry is suffering high losses. In view of the argument of interested parties, the Authority has considered the information on profit/loss provided in the application since 2007-08 along with applicable customs duty. It is observed that the domestic industry was earlier in profits when there was no or low concession and the domestic industry has now been suffering financial losses when Korean imports have full concessions, as shown below:

Year	Customs duty	Profit/loss
	%	Trend Rs/MT
2007-08	10.00%	100
2008-09	10.00%	151
2009-10	10.00%	98

2010-11	6.88%	216
2011-12	5.00%	41
2012-13	4.38%	159
2013-14	1.88%	43
2014-15	0.00%	-52
2015-16	0.00%	-60
2016-17	0.00%	-39
2017-18	0.00%	-3
2018-19	0.00%	-20
Apr'19-Jun'19	0.00%	17
Jul'19-Sep'19	0.00%	-33
Apr'19-Sep'19	0.00%	-7

g. Price undercutting

44. It was examined whether the imports from Korea were benchmarking the prices of the product in the market. For the purpose, the landed price of imports from various countries were compared with the landed price of imports from Korea and selling price of domestic industry. The Director General also examined whether the effect of Korean imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of Korean imports has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and depression.

S.No.	Year	Landed Price				Selling Price of DI
		Korea RP	ASEAN countries	Japan	Other Countries	
		Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	Trend Rs/MT
1	2015-16	89,939	87,099	83,903	89,590	100
2	2016-17	1,14,176	1,21,863	99,444	1,08,450	145
3	2017-18	1,28,169	1,32,194	1,65,028	1,35,062	141
4	2018-19	1,33,118	1,34,850	1,35,202	1,36,999	150
5	Apr'19-Jun'19	1,08,887	1,09,597	1,22,086	1,20,920	124
6	Jul'19-Sep'19	1,08,909	1,10,581	1,16,364	1,16,611	123
7	April to Sept.,19	1,08,897	1,10,024	1,18,620	1,18,921	124

S.No.	Year	Landed Price- Indexed				Domestic Selling Price - Indexed
		Korea RP	ASEAN Countries	Japan	Other countries	
1	2015-16	100	97	93	100	100
2	2016-17	100	107	87	95	145
3	2017-18	100	103	129	105	141
4	2018-19	100	101	102	103	150
5	Apr'19-Jun'19	100	101	112	111	124
6	Jul'19-Sep'19	100	102	107	107	123
7	April to Sept.,19	100	101	109	109	124

45. It is seen that whereas earlier it were import price from rest of the world which were lower than or equal to the import price from Korea, from 2017-18, when the Korean exports received full duty concession benefits, it was Korean prices which were lower than the import price from rest of the world. Further, the landed price of imports from Korea RP has been lower than the selling price of the domestic industry, thus establishing that the domestic industry has been forced to benchmark its prices with the import prices from Korea RP.

46. Landed price of imports from Korea RP are lower than the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices.

S.No.	Year	NSR	Landed price	Price Undercutting	Price Undercutting
		Trend Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	%
1	2015-16	100	89,939	*****	2.5-12.5%
2	2016-17	145	1,14,176	*****	15-25%
3	2017-18	141	1,28,169	*****	2.5-12.5%
4	2018-19	150	1,33,118	*****	2.5-12.5%
5	Apr'19-Jun'19	124	1,08,887	*****	5-15%
6	Jul'19-Sep'19	123	1,08,909	*****	5-15%
7	April to Sept.,19	124	1,08,897	*****	5-15%

47. The table below shows the comparison of cost of production, selling price of the domestic industry with the landed price of imports from Korea RP.

S.No.	Year	Cost of Sale	Selling price	Landed price-Korea RP
		Trend Rs/MT	Trend Rs/MT	Rs/MT
1	2015-16	100	100	89,939
2	2016-17	135	145	1,14,176
3	2017-18	122	141	1,28,169
4	2018-19	134	150	1,33,118
5	Apr'19-Jun'19	102	124	1,08,887
6	Jul'19-Sep'19	115	123	1,08,909
7	April to Sept.,19	108	124	1,08,897

48. It is seen that the prices offered by the Korean producers were below not only the selling price of the domestic industry, but also the cost of production of the domestic industry except in the year 2017-18 and Apr19-Jun19 quarter.

F. Conclusion on Injury

49. From the above analysis, it is thus provisionally concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms, in relation to total imports in India as also in relation to the Indian production and consumption. As a result of significant surge in imports from Korea RP, and as the duty concession increased, the domestic industry has suffered serious injury in terms of stagnating sales, declining market share, significant financial losses and negative return on investments. Considering the performance of the domestic producer in respect of various parameters, it is provisionally concluded, pending further investigations that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from Korea at low prices.

G. Causal Link

50. A comprehensive evaluation of performance of the domestic industry, as brought out hereinabove demonstrates that domestic industry has suffered serious injury. It was examined whether the injury to the domestic industry is due to duty concessions and consequent increase in imports from Korea RP. Further, in view of the arguments of the interested parties that the Director General is required to examine whether the claimed injury is on account of duty concessions or some other factors, the Director General also considered the performance of the domestic industry over longer period, including the period when there was no duty concession. Relevant information on this account is contained in the application filed by the domestic

industry, which is also accessible to the interested party through access to the public version of the application.

- a. It was examined whether any other factor could have caused serious injury to the domestic industry. The Director General considered various known parameters and parameters brought by the interested parties and concluded that the reported injury to the domestic industry is not due to possible existence of other factors operating at the same time.
 - b. The imports of product under consideration have increased significantly with increase in tariff concessions to the Korean imports and the eventual elimination of customs duty.
 - c. With full duty concessions, the landed price of Korean import is lower than the landed price of imports from rest of the world and selling price of the domestic industry. It was the Korean prices which were benchmarking the prices of the product in the market, being the lowest.
 - d. While the production and capacity utilization of the domestic industry has increased, the domestic sales of the domestic industry has not increased with the rising imports as a consequence of duty concessions. The stagnating domestic sales and rising exports at less favourable prices are a result of increase in imports in India.
51. It is thus provisionally concluded that injury to the domestic industry has been caused by increased Korean imports and there exists a causal link between increased imports of subject goods from Korea and serious injury to the domestic industry.

H. Critical Circumstance

52. Rule-8 of Bilateral Safeguard Rules provides that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, where there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional bilateral safeguard measure would cause damage to the domestic industry which would be difficult to repair, the Director General may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a result of increased imports of an originating good. The Director General holds that the following facts establish the existence of critical circumstances warranting imposition of interim safeguard measures.
- a. With duty concessions increasing to full extent in 2017-18, share of imports of the product from Korea RP in total imports surged from 16% in 2007-08 to 37% in 2016-17 and to 54% in 2017-18 and have remained at that high levels thereafter.
 - b. With significant duty concessions during the present period, the domestic industry has been suffering significant financial losses, leading to negative return on investment.
 - c. Though domestic industry could produce the product under consideration, it is unable to proportionately increase its domestic sales despite increase in domestic demand of the product under consideration. As a result, the domestic industry has been forced to export the subject goods at a price lower than domestic selling price.
 - d. Market share of the domestic industry has declined significantly.
 - e. As a result, domestic sales of the domestic producer further declined significantly in the most recent period (July-Sept., 2019 period). Further, profitability of the domestic industry has also suffered significantly in this period. The sales volumes in July-Sept., 2019 were 14% lower than volumes sold in 2016-17.
 - f. The domestic industry has been forced to export the subject goods at a price lower than the domestic selling price.
53. It is noted that the factors present constitute critical circumstances and are affecting the overall performance of the Indian industry, justifying imposition of provisional bilateral safeguard measure.

I. Adjustment plan

54. Applicant has provided details of the adjustment plan during the course of the investigations. The applicant has quantified that it shall take measures directed towards reducing costs on a number of accounts. The Applicant has identified action plan directed at catalyst & chemicals cost reduction, conversion cost reduction, improvement in process efficiency, improvement in consumption norms, reduction in transportation costs, improvement in turnaround of stocks, etc. The Authority considers that the Applicant has drawn an adjustment plan to become import competitive.

J. Conclusion and Recommendation

55. On the basis of the preliminary examination above, it is provisionally concluded that increased imports of subject goods have caused serious injury to domestic producers. It is considered that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measures would cause irreparable damage to the domestic producer. With regard to imposition of bilateral safeguard measure, Rule 9 of - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows:

(1) The Central Government, on the basis of the preliminary findings of the Director General, may -

(a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for under the Trade Agreement; or

(b) increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:

(i) the Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the originating good in effect at the time when the bilateral safeguard measure is taken; and

(ii) the Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the originating good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement.

(2) The bilateral safeguard measure under sub-rule (1) shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date of its imposition.

56. After examining the above, it is considered appropriate to recommend provisional bilateral safeguard measure in terms of Rule 9 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, pending final determination, the Authority provisionally recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods originating in Korea RP to the level of MFN duty on the subject goods as on the date of application of the bilateral safeguard measure or MFN duty on the subject goods on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement, whichever is less
57. The provisional bilateral Safeguard measure on the import of the said product, as above, is proposed to be levied for a period of 200 days (two hundred days).

K. FURTHER PROCESS

58. The following further procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:
- The Director General invites comments on preliminary findings from all known interested parties within 30 days from the date of issue of preliminary findings. The comments received from them would be examined in the final findings.
 - The Director General would conduct an oral hearing to provide an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
 - The Director General would conduct verification to the extent deemed necessary.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Director General